दुष्यंत के विरोध के पीछे जेजेपी को दिखा कांग्रेस का हाथ

वे फूल बरसाएँगे, हम काले झंडे दिखाएँगे : किसान

बल्लभगढ़, (चन्द्र प्रकाश): नरियाला गांव में 21 मार्च को होने वाले होली मिलन कार्यक्रम के विरोध के पीछे जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के स्थानीय नेता कांग्रेस का हाथ देख रहे हैं। होली मिलन के नाम पर होने वाले इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बुलाया गया है। लेकिन कार्यक्रम की घोषणा होते ही किसान संघर्ष समिति ने आयोजन का विरोध कर दिया और कहा कि वे दुष्यंत को गांव में घुसने नहीं देंगे। बेहतर होगा कि डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में शिरकत न करें।

जेजेपी के जिला अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज का कहना है कि ये विरोध कांग्रेस के लोगों की साजिश है। वे दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। दुष्यंत भविष्य के नेता हैं। हरियाणा की राजनीति में उनका मुकाबला नहीं। कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, इस तरह की राजनीति से उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है।

किसान संघर्ष समिति ने अपनी 16 मार्च की पंचायत में उपमुख्यमंत्री के आगमन पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रकट करने का फैसला लिया। हरियाणा किसान संघर्ष समिति के कार्यकर्ता सदस्य रूपराम मोहना ने बताया कि जहां-जहां जेजेपी पार्टी के विधायक जीते हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में लोग उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। लोगों की नाराजगी को देखते हुए सीएम तक को अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। लेकिन जिस पृथला विधानसभा में जेजेपी का कोई जनाधार नहीं है उसमें कुछ पार्टी के कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला को बुलाकर क्या साबित करना चाहते हैं। गत विधानसभा चुनावों में शशिबाला तेवतिया जेजेपी की कर्मठ उम्मीदवार थीं, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली और वर्तमान विधायक नयनपाल रावत के समर्थन में बैठ गईं थीं।

रूपराम मोहना ने कहा, वही पार्टी अब पृथला में जनसभाएं कर रही है। इलाके में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के प्रति आम जनता में रोष है। किसान पिछले चार माह से धरने पर है। मोदी सरकार उसे कभी खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी बता रही है। किसान अपना घर-बार छोड़कर सड़कों पर पड़े हैं और नेताजी होली मिलन समारोह मना रहे हैं। यह सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, वे फूल मालाओं से उपमुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, हम काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराएँगे।

उधर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन डागर का कहना है कि प्रदेश के हर ज़िले में लोग सरकार के विरोध में खड़े हैं। हरियाणा किसान संघर्ष समिति किसानों के हक और अधिकारों के लिए लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। वह दिन अब दूर नहीं जब जनता इन्हें सबक सिखाएगी।

धर्मार्थ अस्पताल अब हुआ सील, धर्मगुरु ने पंजाबी बिरादरी के एक गुट को....

पेज एक का शेष

चेरिटेबल सोसायटी पर कब्जे को लेकर नहीं है। इसके पीछे पैसे की बंदरबांट है। दरअसल बंद होने से पहले इस अस्पताल को तीन से पांच लाख रुपये महीने की आमदनी थी। लेकिन अस्पताल में तमाम निर्माण और अन्य काम के नाम पर सारे पैसे का खर्च विभिन्न मदों में दिखा दिया जाता था। यहां तक की पीएफ की 75000 रुपये की रकम का फर्जी भुगतान की कच्ची रसीद काटी गई। जिन लोगों ने डोनेशन के पैसे दिए, उन्हें सदस्य बना दिया गया. सदस्यता की रसीद पर यह दर्ज नहीं है कि जो रकम ली जा रही है वो किस मद में ली जा रही है। ज्यादातर रसीदों पर दो लोगों के हस्ताक्षर हैं। सोसायटी के सदस्य इन्हें चाचा-भतीजा की जोड़ी कहते हैं।

अनाप-शनाप खर्चों के लिए काटी गई रसीदों के मुद्दे को उप प्रधान विशाल भाटिया ने चुनौती दी। उन्होंने प्रधान से कहा कि सारी पेमेंट चेक के जरिए या बैंक पेमेंट के माध्यम से दी जाए। किसी भी तरह के कैश का लेन-देन न हो। इसके बाद विशाल भाटिया और सोसायटी के तमाम सदस्यों ने निलंबित प्रधान कंवल खत्री से विभिन्न खर्चों की रसीदों का हिसाब मांगा। इसके बाद दोनों पक्षों में अनबन शुरू हो गई। हालांकि कंवल खत्री गुट अपने बचाव में यह कहता रहा है कि कुछ खर्चों की पेमेंट चेक के जरिए नहीं हो सकती। उसके लिए कैश का सहारा लेना ही पड़ेगा। जबकि इस मामले में तीसरा पक्ष और भाजपा नेता आनंदकांत भाटिया का कहना है कि कैशलेस पेमेंट बहुत आसानी से संभव है। लेकिन उसके लिए सोसायटी को पहले अपना कार्यकलाप बदलना पड़ेगा।

सूत्रों का कहना है कि अस्पताल के साथ ही केमिस्ट शॉप भी है। सोसायटी के एक गुट के लोग इसमें साइलेंट पार्टनर हैं। इससे भी सोसायटी के उस गुट को मोटी आमदनी हो रही थी। लेकिन अस्पताल पर ताला लगने के बाद केमिस्ट शॉप भी ठप्प पड़ी है।

पीर जगन्नाथ के दरबार में फिर पहुंचा मामला

निलंबित प्रधान कंवल खत्री गुट ने सोमवार को पंजाबी बिरादरी के लोकल धर्मगुरु पीर जगन्नाथ से मुलाकात कर अस्पताल की चाबी उन्हें सौंपने की मांग रखी। लेकिन पीर जगन्नाथ ने खत्री के साथ आये लोगों को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि रिश्तेदारी के बावजूद वह किसी एक गुट को खुश नहीं कर सकते। सरकार जिसे प्रधान घोषित करेगी, उसको अस्पताल की चाबी सौंप दी जाएगी। लेकिन किसी भी गुट का पक्ष नहीं सकते। बिरादरी को ऐसे मामलों में खुद ही सूझवान होना चाहिए।

सूत्रों का कहना है कि अगर दोनों पक्ष इस मामले को सरकारी स्तर पर सुलझाने की कोशिश करते रहे तो यह मामला और उलझेगा। लेकिन अगर दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी शिकायतें वापस लेकर तब पीर जगन्नाथ के जरिए इस मामले को बिरादरी के आधार पर सुलझा सकते हैं। अस्पताल चूंकि बृजमोहन भाटिया परिवार के योगदान से बना है तो कोई भी पक्ष इसमें उस परिवार को नजरन्दाज करके कब्जा नहीं कर सकता।

शहर के लोग चाहते हैं अस्पताल चले

शहर की पंजाबी बिरादरी का कहना है कि यह अस्पताल चलना चाहिए। पंजाबी बिरादरी के अधिकांश लोग अपना कारोबार करते हैं। उनकी दुकानों और दफ्तरों पर कम वेतन पाने वाले कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा शहर में बहुत बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग रहता है। इस अस्पताल में सिर्फ 20 रुपये की पर्ची और विभिन्न टेस्ट के सस्ते रेट की वजह से इस वर्ग में इस अस्पताल का महत्व बराबर बना हुआ है। लेकिन इस तबके के लोग अस्पताल पर ताला लगाकर देखकर लौट जाते हैं। पूरे कोरोना काल से लेकर अब तक यह अस्पताल सोसायटी पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बंद पड़ा है।

जितेन्द्र भाटिया का कहना है कि सोसायटी का मसला हल होता रहेगा, बेहतर है कि इस अस्पताल को बीके अस्पताल या हरियाणा सरकार टेकओवर कर ले। कम से कम गरीबों को इलाज तो नसीब हो सकेगा।

नवल भाटिया का कहना है कि सोसायटी बिरादरी से बड़ी नहीं है। अगर यह लड़ाई पैसे की नहीं है तो अस्पताल फौरन खोला जाए। जुगल भाटिया का कहना है कि बिरादरी के पैसों को इस तरह खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया जाएगा। अगर सोसायटी पाक-साफ है तो वह अस्पताल क्यों नहीं चलने देती। उनका कहना है कि असली चुनौती तो अस्पताल की जमीन है। क्योंकि अब सील भी लग चुकी है। पंजाबी बिरादरी के इतने लोग नेता बने घूम रहे हैं, कुछ विधायक भी हैं, कुछ भूतपूर्व भी हो चुके हैं, ये सभी लोग क्यों नहीं मिलकर सरकार पर इस जमीन के लिए दबाव बनाते।

भगत सिंह से दोस्ती की.....

पेज एक का शेष

हड़प जाते हैं। अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने-दाने के लिए मोहताज हैं। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया करने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के तन ढ़कने भर को भी कपड़ा नहीं पा रहा है। सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ई स्वयं गंदे बाड़ों में रहकर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं। इसके विपरीत समाज के जोंक, शोषक पूंजीपति जरा-जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा-न्यारा कर देते हैं। "यह भयानक असमानता और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल-पुथल की ओर लिए जा रहा है । यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती है। भारत सरकार का प्रमुख लॉर्ड इरविन की जगह यदि सर पुरुषोत्तम दास, ठाकुरदास हो तो जनता को क्या फर्क पड़ता है।"

भगत सिंह ने मेहनतकशों की तत्कालीन दशा, आजादी के संघर्षों की दिशा को परिभाषित करते हुए अंग्रेजों की जगह भावी समाज व्यवस्था के बारे में ठोस रूप में बताया है। अंग्रेजों गुलामी से मुक्ति के 70 सालों बाद भी भगत सिंह के कथन आज भी सही है। कुछ नया है तो अंग्रेजों की जगह देसी पूंजीपतियों/ शासकों की सत्ता। गोरी बुराई की जगह काली बुराई।

देश का अपना एक संविधान है। बड़ी जद्दोजहद के बाद मेहनतकशों को कुछ अधिकार मिले। सभी को बेहतर शिक्षा, और स्वास्थ्य देने की बात कही गई। इसमें जीने का मौलिक अधिकार भी दर्ज है। लेकिन पिछले तीन दशकों से लागू निजीकरण की नीतियों के द्वारा देश के उद्योगों, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों को देसी- विदेशी पूंजीपतियों/कारपोरेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है। मोदी सरकार ने श्रम कानूनों की जगह चार श्रम संघिताएं लाकर मजदूरों के अधिकारों को बहुत कम कर मालिकों को शोषण का और अधिकार दे दिया है। नए कृषि कानून बनाकर खेती किसानी को कारपोरेट कंपनियों को सौपने पर मोदी सरकार अड़ी है। शिक्षा-स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार की स्थिति सबके सामने है। महिलाओं बच्चियों पर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। मौजूदा शासक वर्ग हिन्दुत्व के सहारे देश में फासीवादी निजाम कायम करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का संघर्ष धीरे-धीरे ही सही, बढ़ रहा है। पिछले 4 माह से किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली को घेरे बैठे हैं। छात्रों, बेरोजगारों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों का गुस्सा भी बीच-बीच में फूट पड़ता है।

आज भगत सिंह के विचारों पर गहन चिंतन मनन करने की तथा समाज में प्रचारित प्रसारित करने की जरूरत है।

गतांक की चीर-फ़ाड़

सत्ता व प्रशासन तंत्र की छत्र-छाया में ठेकेदार, बेइमान व निकम्मे अफ़सर

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 14-20 मार्च 2021 के अंक में समसामयिक मुद्दों पर अनेक समाचार व लेख प्रकाशित हुए है। फ़रीदाबाद में ददसिया रेनीवेल की पाइप लाइन टूटने से नगर के 12 से अधिक सेक्टरों तथा कई कॉलोनियों में कई दिनों तक भीषण पेयजल के संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन एमसीएफ़ के बजट में पेयजल सप्लाई पर खर्च करने के प्रावधान के बावजूद पेयजल की आपूर्ति दुरूस्त नहीं की जाती, जिसका 'फ़रीदाबाद में पानी की पाइप लाइन तोड़ों और पैसा कमाओ-रेनीवेल लाइन टूटने पर एमसीएफ़ अफ़सरों की होती पौ-बारह' में खुलासा किया गया है।

एक सर्वे के अनुसार रेनीवेल लाइन के 160 पॉइन्ट पर 60 के करीब पंप खराब हैं और कई रेनीवेल में तो पानी सूख ही चुका है। एमसीएफ़ द्वारा खराब पंप और रेनीवेल को ठीक नहीं कराए जाने के कारण लोग प्राइवेट टैंकरों के हाथों लुटने के लिये मजबूर हो जाते हैं।

सत्ता व प्रशासन तंत्र की छत्र-छाया में ठेकेदार, बेइमान व निकम्मे अफ़सर तथा पानी बेचने वाले माफ़िया की मिलीभगत से सरकारी व जनता के पैसे की लूट व गोरखधंधा एक संगठित तरीके से किया जा रहा है।

इन सबके बावजूद भाजपा का आईटी सेल और मोदी समर्थक मीडिया दुनिया के 70 से ऊपर देशों को कोविड वैक्सीन भेजने के अलावा पाकिस्तान को मुफ्त कोविड वैक्सीन देने व कोविड आपदा से निपटने का श्रेय मोदी सरकार को देने का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।

'न्यायपालिका पर अन्यायपूर्ण पुलिसिया दबाव को मैंने खुद देखा' में मज़दूर मोर्चा के सम्पादक सतीश कुमार ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बेगुनाह व्यक्तियों पर झूठा केस बना कर उन्हे जेल भेजने के लिए पुलिस द्वारा अदालत की चापलूसी करने, नाजायज दबाव डालने व विभिन्न हथकंडे अपनाने की कार्यशैली का पर्दाफ़ाश किया गया है।

कानपुर की ग्रामीण नाबालिग लड़की का एक दारोगा के बेटे और उसके दोस्तों द्वारा अपहरण कर सामुहिक बलात्कार करने व पीड़ित लड़की के पिता की ट्रक द्वारा कुचले जाने से मौत, बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जानलेवा हादसे में गंभीर चोटें लगना तथा वी-डेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में भारत को लोकतंत्र की बजाए राजनीतिक तानाशाही वाला देश बनाने के संदर्भ में 'राजनीतिक तानाशाही का सबूत है कानपुर और नंदीग्राम की घटना' में मोदी सरकार के कार्यकाल में राजनीतिक तानाशाही स्थिति का सटीक विश्लेषण किया गया है।

अमेरिकी एनजीओ फ्रीडम हाउस ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में मानवाधिकार संस्थाओं, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों पर दबाव बढ़ने और उन्हें भयभीत करने की घटनाओं में वृद्धि होने तथा अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों के खिलाफ़ मौब लिंचिंग और कट्टर धर्मांधता की घटनाएं बढने से नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता व न्यायिक स्वाधीनता का पतन होने से भारत की रेटिंग 'स्वतंत्र प्रजातंत्र' से घटाकर 'आंशिक प्रजातंत्र' कर दी है।

ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्रोजेनेक की कोविड वैक्सीन के टीकाकरण के बाद कुछ लोगों में खून के थक्के जमने की खबरों के बाद आस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी व स्पेन समेत 17 देशों ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जबकि कंपनी, यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इस टीके के इस्तेमाल को बंद करने का कोई कारण नहीं है। भारत में भी सरकार के बयान के मुताबिक उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, यूपी आदि कई राज्यों में 50 से भी अधिक लोगों की टीकाकरण के बाद मौत हो चुकी है लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मौत की वजह टीकाकरण नहीं है। 'कोविशील्ड के टीके के बाद भारत में अब तक दर्जनों मौतें' तथा 'पाकिस्तान को भारत की मुफ़्त वैक्सीन का सच' में कोबिड के खिलाफ़ वैक्सीन के इस्तेमाल और सप्लाई की हकीकत से अवगत कराया गया है।

टीकाकरण के बाद हुई मौतों को अक्सर टीकाकरण से सम्बन्धित होने की बजाय हार्ट अटैक से बताया जाता है, जबकि खून का थक्का जमने और हार्ट अटैक का आपस में गहरा सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज के टीकाकरण के बाद भी कोविड पॉजीटिव होने की खबरें आ रही है। इसलिए इस वैक्सीन की क्षमता की जांच करवाने की आवश्यकता है।

अदालतों में पुलिस द्वारा पेश किए केस में जज अक्सर पीड़ित को जमानत देने की बजाए पुलिस द्वारा मांगी गई पुलिसिया हिरासत को तुरंत मंजूर कर देते हैं, जिससे पीड़ित पुलिस व जेल की यातनाएं सहने को मजबूर हो जाता है। फ़रवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरली धरण ने दिल्ली पुलिस को फ़टकार लगाते हुए जवाब-तलब करने के लिए अगली पेशी पर पेश होने का नोटिस देने से मोदी सरकार ने नाराज होकर उस जज को रातों-रात चंडीगढ ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे माहौल में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सेशन जज धर्मेन्द्र राणा तथा गुड़गाव के अतिरिक्त सेशन जज अश्विनी कुमार द्वारा अपने फ़ैसलों में पुलिस को लताड़ लगाने वाले जज वास्तव में अंधकार में रोशनी की किरण जैसे हैं जो अन्य जजों के लिये भी आदर्श बनेंगे जिससे वे भी निडरता व निष्ठापूर्वक न्याय करने का साहस कर सकें।